हैं जो जगह जगह जाकर ग्राहकों को सस्ते दामों पर चीजें बेचते हैं । लेकिन सवाल यह उठता है कि इस तरह के वैन्स कितनी चीज लादकर जगह जगह ले जायेंगे । कलकत्ते और बम्बई में इस तरह के जो वैन्स चल रहे है, उनको इसमें बहुत कामयाबी नहीं मिली है ।

*529. [*The questioner (Shri S. K. Vaishampayen) was absent. For answer*, vide *col.* 4059 infra.]

REPORT OF AGRICULTURAL PRICES COMMISSION

*530. SHRI ABDUL GHANI: Will the Minister of FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) whether Government have received the report of the Agricultural Prices Commission;

(b) if so, the main recommendations thereof; and

(c) the decision taken by Government on the recommendations of the Commission?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI P. GOVINDA MENON): (a) to (c) The Agricultural Prices Commission has submitted reports and made recommendations on price policy for different agricultural commodities for 1965-66 and 1966-67 seasons. The main recommendations relate to the level of minimum prices. For such commodities as are purchased by Government, the Commission has made recommendations on purchase prices and other policy aspects. The Commission's recommendations have generally formed the basis of Government's decisions announced from time to time.

شری عبدالغنی : کیا وزیر صاحب فرمائینگے کہ ان کی رپورٹ نے مختلف کموڈیٹیز کے لئے کم سے کم قیمت مقرر کرنے کی سفارش کی ہے - اگر کی ہے تو اس نے کموڈیٹیز کیا ہیں اور اس پر سرکار نے آیا کوئی عمل کرنے کی طوف قدم اٹھایا ہے اور اگر اٹھایا ہے تو کیا کیا ہیں -

†[श्री अब्दुल गनी : क्या वजीर साहब फरमाएंगे कि उनकी रिपोर्ट ने मुख्तलिफ कमोडिटीज के लिए कम से कम कीमत मुकर्रर करने की सिफारिश की है । अगर की है, तो उसके डिटेल्स क्या हैं और उस पर सरकार ने आया कोई अमल करने की तरफ कदम उठाया है और अगर उठाया है, तो क्या क्या है ?]

SHRI P. GOVINDA MENON: The recommendations regarding minimum prices which are in the nature of support prices have been accepted by Government.

شری عبدالغنی - انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا - میرا سوال یہ تھا کہ انہوں نے مختلف کموڈیٹیز جیسے وھیٹ - رائس - پیڈی - گرام - باجرا - جوار اور میز ھیں ان کی کم سے کم قیمت مقرر کی ہے - اگر کی ہے تو وہ کیا ہے اور اس پر سرکار نے کیا قدم اٹھائے ھیں ؟

†[श्री अब्दुल गनी : उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया । मेरा सवाल यह था कि उन्होंने मुख्तलिफ कमोडिटीजजैसे व्हीट, राइस, पैडी, ग्राम, बाजरा, जवार और मेज़ हैं, उनकी कम से कम कीमत मुकर्रर की है । अगर की है तो वह क्या है और उस पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?]

†[ ] Hindi transliteration.

SHRI P. GOVINDA MENON: Support prices have been accepted as recommended by the Commission.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have not put a ceiling on the prices.

SHRI P. GOVINDA MENON: No, Madam.

شری عبدالغنی : میرے سوال کا جواب اب بھی نہیں آیا - میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا تو کیا کہا ہے - انہوں نے مینیمم کہا ہے - تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مینیمم پرائس کیا ہے - ملک والے اس پارلیمنٹ کے ذریعہ جاننا چاہیں گے کہ مینیمم پرائس کیا ہے اور اس پر سرکار نے کیا کیا ہے -

[†**श्री अब्दुल ग़नी** : मेरे सवाल का जवाब अब भी नही आया । मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा तो **क्या** कहा है? उन्होंने मिनिमम कहा है । तो **में यह** जानना चाहता हूं कि यह मिनिमम प्राइस क्या है? मुल्क वाले **इस** पार्लियामेंट के जरिए जानना चाहेगे कि **मिनिमम** प्राइस क्या है और इस पर सरकार ने क्या किया है ?]

SHRI P. GOVINDA MENON: Minimum prices are in the nature of support prices, that is to say, if the prices of certain commodities go below that level, Government will be prepared to purchase those commodities at that price.

That is the minimum price. I correct myself regarding something I said earlier. There are in certain States maximum prices fixed.

श्री रांजनारायण : माननीया, मंत्री जी जो उत्तर दे रहे हैं, उसी को उत्तर माना जाय ?

उपसभापति : आपको जो पूछना हो, उसको पूछिये ।

†[ ] Hindi transliteration.

श्री राजनारायण : मैं समझता हू कि इस पर मंत्री जी की भर्त्सना करनी चाहिये ।

उपसभापति : आप जवाब के ऊपर सवाल पूछिये ।

श्री राजनारायण : जवाब कोई है ही नहीं । मंत्रियों को तैयार हो करके आना चाहिये । मेरा सवाल यह है कि गेहूं का दाम तय करने के लिये किन किन बातों को कंडीशन बनाया गया है और क्या सरकार के पास कोई ऐसा भी सुझाव गया है जिले मे कहा गया है कि गल्ले की कीमत तय करने के पूर्व खाद्य, पानी, जमीन, मेहनत और जांगर सबकी कीमत जोड़ कर गल्ले की कीमत तय हो और उसमें रेम्युनरेशन भी किसान को मिले और जिस भाव पर किसान से गल्ला लिया जाय उससे चार पैसा फी सेर से ज्यादा फर्क पर वह गल्ला किसी दूकान पर न बिकने दिया जाय ? क्या यह कंक्रीट प्रोपोजल सरकार के पास संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की ओर से गया है और अगर गया है तो सरकार ने इस पर क्या किया ?

Shri P. GOVINDA MENON: I am not aware whether the SSP has made any representation regarding the prices fixed. There are two sets of prices.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Is there a recommendation to that effect from this Commission?

SHRI P. GOVINDA MENON: The Commission recommended minimum prices, that is, support prices.

شری نریندر سنگھ برار - دیکھئے -- جہاں تک راج نرائن جی کا تعلق ہے انہوں نے بہت درست سوال اٹھایا ہے کہ جو بھی قیمت مقرر کی جائے وہ کسانوں کے پیداوار کو مدنظر رکھ کر ان کی مشکلات کو مدنظر رکھ کر اور ان کے خرچہ کو

مدنظر رکھ کر مقرر کی جائے - اس کے بعد پھر گورنمنٹ کو نو لوس نو پرافٹ کے حساب سے غلہ کو بیچنا چاہیے اور اس کے لئے پابندی ہونی چاہئے تاکہ بیچ والے زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکیں — میرا سیکنڈ سوال یہ ہے کہ جہاں تک کاٹن کا تعلق ہے - کاٹن کرئی کھانے پینے والی چیز نہیں ہے لیکن اس پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے جب تک کہ کاٹن پروڈیوسر کے ہاتھ میں ہوتی ہے - لیکن جب وہ کارخانہدار کے پاس چلی جاتی ہے تو اس کی پرائس کئی گنا تک چلی جاتی ہے اور ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ آج کسان کی کوئی آواز نہیں ہے اور اس سے جو ووٹ لیتے ہیں اسشوپیلی رولنگ پارٹی وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں -

†[**श्री नरेन्द्र सिंह ब्रार** : देखिए, जहां तक राज नारायण जी का ताल्लुक है, उन्होंने बहुत दुरूस्त सवाल उठाया है कि जो भी कीमत मुकर्रर की जाए वह किसानों के प्रोफिट को मद्दे-नजर रख कर, उनकी ही मुश्किलात को मद्दे-नज़र रख कर और उनके खर्चे को मद्दे-नज़र रख कर मुकर्रर की जाए। उस के बाद फिर गवर्नमेंट को नो लास, नो प्रोफिट के हिसाब से ग़ल्ले को बेचना चाहिए और उस के लिए पाबन्दी होनी चाहिए ताकि बीच वाले ज्यादा फायदा न उठा सकें। मेरा सेकंड सवाल यह है कि जहां तक काटन का ताल्लुक है, काटन कोई खाने पीने वाली चीज़ नहीं है लेकिन इस पर भी पाबन्दी लगा दी जाती है जब तक कि काटन प्रोड्यूसर के हाथ में होती है। लेकिन जब वह कारखानेदार के पास चली जाती है, तो उसकी प्राइस कई गुना तक चली जाती है और ऐसा इसलिए होता है कि आज किसान की कोई आवाज़ नहीं है और इस से जो वोट लेते हैं, स्पेशियली रूलिंग पार्टी वह इस बात का खयाल नही रखते हैं] . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ask a question. (*Interruptions*).

SHRI NARINDAR SINGH BRAR: Try to listen to me.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You please come to the question.

شری نریندر سنگھ برار - انہوں نے کبھی اس سوال کو نہیں اٹھایا کیونکہ کسان کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہوتی ہے - صرف گرو مور فوڈ کہنے سے کام نہیں چلے گا - یہ گورنمنٹ کا فرض ہے اور ہمارا فرض ہے کہ کاٹن پر جو پابندی لگائی جاتی ہے یا لانگ اسٹیپل کاٹن پر جو پابندی لگائی جاتی ہے اس کو روکا جائے -

†[**श्री नरेन्द्र सिंह ब्रार** : उन्होंने कभी इस सवाल को नहीं उठाया, क्योंकि किसान की कोई आर्गेनाइज़ेशन नहीं होती है। सिर्फ ग्रो मोर फूड कहने से काम नहीं चलेगा। यह गवर्नमेंट का फर्ज़ है और हमारा फर्ज़ है, कि काटन पर जो पाबन्दी लगाई जाती है या लौंग स्टेपिल काटन पर जो पाबन्दी लगाई जाती है, उसको रोका जाए।]

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is all right. I think what he has given is a lot of information.

شری نریندر سنگھ برار - کسانوں انسینٹیو دینے کے لئے ایسی

†[ ] Hindi transliteration.

پرائس مقرر کی جائے جس سے ان کو فائدہ پہنچے -

†[श्री नरेन्द्र सिंह बारः किसानों को इंसेन्टिव देने के लिए ऐसी प्राइस मुकर्रर की जाय, जिस से इनको फायदा पहुंचे ।]

THE DEPUTY CHAIRMAN: Have you got any system by which you have assessed all these?

SHRI P. GOVINDA MENON: What I have said is . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has given you a lot of information and said that you have not taken a complete assessment of how much the cost would be to the farmer.

SHRI P. GOVINDA MENON: I will accept that information. That will be considered.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have not considered it up till now? Next question.

شری عبدالغنی : میڈم میرے سوال کا جواب نہیں ملتا -

†[श्री अब्दुल गनी : मैडम, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता ।

उपसभापति : नहीं मिलता तो क्या करें ।]

شری عبدالغنی - یہ حکم دیجئے کہ اگر یہ اسٹڈی کر کے نہیں آ سکے تو پھر اسٹڈی کر کے آئیں اور ھاؤس کو بتائیں تاکہ ھاؤس کو پتہ چلے - ابھی تو انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا --

†[श्री अब्दुल गनी : यह हुक्म दीजिए कि अगर यह स्टडी करके नहीं आ सकते, तो फिर स्टडी करके आयें और हाउस को बतायें ताकि हाउस को पता चले । अभी तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया ।]

†[ ] Hindi transliteration.

SHRI P. GOVINDA MENON: What is the question? Does the hon. Member want . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have followed the question and also the information given by the hon. Member. Have you got any information with you now or, are you acting on all the suggestions that have been made or they are suggestions for action?

SHRI P. GOVINDA MENON: I understood his question to be whether the producer is being given a remunerative price. My submission is that it is being done. But I am free to admit that there are complaints that the price offered is not good enough.

***531.** [*The questioner (Shri Sundar Singh Bhandari) was absent. For answer,* vide *cols.* 4059-4060 infra]

REMOVAL OF SUBSIDY ON IMPORTED FOODGRAINS

*532. SHRI BABUBHAI M. CHINAI: Will the Minister of FOOD AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION be pleased to state the saving in expenditure as a result of the removal of subsidy on imported foodgrains?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI P. GOVINDA MENON): Imported foodgrains continue to be sold at subsidised rates. As such the Question of any saving in expenditure on account of removal of subsidy does not arise.

SHRI BABUBHAI M. CHINAI: May I know what is the extent of the removal of subsidy on imported wheat and rice?

SHRI P. GOVINDA MENON: Regarding wheat, the issue price per quintal is Rs. 48 from 1st January, 1965 to 14th November, 1965; Rs. 50 from 15th November, 1965 to 14th November, 1966; Rs. 55 from 15th November, 1966 onwards. As re-